'फिट ऐंड प्रॉपर' व्यवस्था में बदलाव की तैयारी

बदलाव का मकसद संबद्ध संस्थान से लोगों की भूमिका अलग करना है

खुशबू तिवारी
मुंबई, 12 जुलाई

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) स्टॉक एक्सचेंज जैसे मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन (एमआईआई) के लिए लागू अपने 'फिट ऐंड प्रॉपर' मानकों में बदलाव पर विचार कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि इस बदलाव का मकसद संबद्ध संस्थान से लोगों की भूमिका अलग करना है।

मौजूदा ढांचे के तहत, वरिष्ठ कर्मी द्वारा गलत तरीका अपनाने से स्टॉक एक्सचेंज, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट और समाशोधन सदस्यों जैसे एमआईआई को प्रतिबंधित किया जा सकता है, जैसा कि पिछले समय में ऐसे कई मामले देखने को मिले हैं।

इसके अलावा, सेबी एक ऐसा क्लॉज लागू करने पर भी विचार कर रहा है, जिसके जरिये एमआईआई के खिलाफ पारित किसी आदेश से उसका परिचालन प्रभावित नहीं होगा, जब तक कि आदेश में इसके बारे में विशेष रूप से जिक्र नहीं किया गया हो।

फिट ऐंड प्रॉपर मानकों से यह निर्धारित करने में मदद मिलती है कि क्या कोई संस्था और व्यक्ति बाजार तंत्र में अपनी महत्ता को देखते हुए एमआईआई का शेयरधारक बनने के लिहाज से पात्र है या नहीं। लोगों को एमआईआई में बड़ी जिम्मेदारियां पाने के लिए फिट ऐंड प्रॉपर मानकों को पूरा करना होगा। कुछ मानकों में निष्पक्षता का रिकॉर्ड, वित्तीय अखंडता, किसी अपराध के लिए किसी अदालत में दोषी नहीं पाया जाना आदि मुख्य रूप से शामिल हैं।

सूत्रों का कहना है कि बाजार नियामक स्टॉक एक्सचेंजेस ऐंड क्लियरिंग कॉरपोरेशंस (एसईसीसी) और डिपोजिटरीज ऐंड पार्टिसिपेंट (डीपी) से जुड़े नियमों में कुछ खास क्लॉज संशोधित करने की योजना बना रहा है। इनमें एमआईआई के शेयरधारकों, निदेशकों और मुख्य प्रबंधन कर्मी (केएमपी) जैसे लोगों के लिए फिट ऐंड प्रॉपर मानक शामिल हैं।

एक अन्य अधिकारी ने कहा, 'फिट ऐंड प्रॉपर पर्सन की परिभाषा में नए क्लॉज को इस तरह से शामिल किया जा सकता है जिससे संबद्ध व्यक्तियों की उपयुक्तता के बारे में आशंकाएं पैदा होने के मामले में इकाइयों पर नियम लागू करने के संबंध में ज्यादा स्पष्टता लाई जा सके।'

यदि अयोग्यता को बढ़ावा देने वाला कोई आदेश निदेशकों, केएमपी या शेयरधारकों के खिलाफ जारी किया जाता है तो इससे एमआईआई के फिट ऐंड प्रॉपर दर्जे पर प्रभाव पड़ सकता है। अधिकारी का कहना है कि चूंकि एमआईआई सार्वजनिक यूटिलिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर सेवा प्रदाता हैं, इसलिए सेबी नहीं चाहता कि उनका परिचालन प्रभावित हो।

सूत्रों का कहना है कि बाजार नियामक ने 28 जून को हुई बैठक के दौरान बोर्ड के समक्ष इस संबंध में प्रस्ताव रखा था।

नए प्रस्ताव के तहत, केएमपी को अयोग्य घोषित किए जाने पर स्टॉक एक्सचेंज या क्लियरिंग कॉरपोरेशन को 30 दिन के अंदर उस व्यक्ति को बदलना होगा, ऐसा नहीं किए जाने पर एमआईआई के खिलाफ भी फिट ऐंड प्रॉपर नियम लागू हो सकता है।

विश्लेषकों का कहना है कि एमआईआई के लिए इस तरह के बदलाव की जरूरत एनएसई में कथित को-लोकेशन मामले के बाद भी महसूस की गई थी।

नए नियम पर विचार

- मौजूदा समय में मुख्य कर्मी या शेयरधारक पर आदेश का एमआईआई के 'फिट ऐंड प्रॉपर' दर्जे पर प्रभाव पड़ सकता है
- सेबी 'फिट ऐंड प्रॉपर' मानकों को अलग कर एमआईआई को प्रमुख कर्मचारियों के किसी भी संभावित प्रतिबंध से बचाने की योजना बना रहा है
- एक ऐसा क्लॉज तैयार करने की योजना है, जिसमें एमआईआई के खिलाफ आदेश से परिचालन प्रभावित नहीं होगा

पतंजलि के प्रवर्तक आज बेचेंगे 9 फीसदी हिस्सेदारी

बीएस संवाददाता
मुंबई, 12 जुलाई

पतंजलि फूड्स की प्रवर्तक पतंजलि आयुर्वेद की योजना गुरुवार को ओएफएस के जरिये 9 फीसदी तक हिस्सेदारी (3.25 करोड़ शेयर) बेचने की है। ओएफएस का मूल आकार 7 फीसदी यानी 2.53 करोड़ शेयर तय किया गया है, जिसमें ज्यादा आवेदन स्वीकार करने का विकल्प है। ओएफएस का फ्लोर प्राइस 1,000 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है, जो आखिरी बंद भाव के मुकाबले 18.4 फीसदी कम है। पतंजलि फूड्स का शेयर 1.1 फीसदी की बढ़त के साथ 1,225 रुपये पर बंद हुआ।

इश्यू का मूल आकार 2,534 करोड़ रुपये का बैठता है। ज्यादा आवेदन मिलने की स्थिति में प्रवर्तक 3,258 करोड़ रुपये तक के शयेर बेचेंगे। ओएफएस से कंपनी को न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता के नियमों का अनुपालन करने मे मदद मिलेगी। अभी कंपनी में प्रवर्तक शेयरधारिता 80.82 फीसदी है। मार्च में स्टॉक एक्सचेंजों ने पतंजलि फूड्स में प्रवर्तक शेयरधारिता को फ्रीज कर दिया था क्योंकि कंपनी तय समयसीमा में न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता के नियमों का अनुपालन करने में नाकाम रही थी। 2019 में पतंजलि आयुर्वेद ने दिवालिया समाधान प्रक्रिया के तहत रुचि सोया का अधिग्रहण किया और उसका नाम बदलकर पतंजलि फूड्स कर दिया। दिवालिया प्रक्रिया के कारण कंपनी में प्रवर्तक हिस्सेदारी बढ़कर 99 फीसदी हो गई थी। मार्च 2022 में बाबा रामदेव की अगुआई वाले पतंजलि फूड्स ने सार्वजनिक शेयरधारिता बढ़ाने की खातिर एफपीओ के तहत 650 रुपये के भाव पर 6.62 करोड़ शेयर जारी किए थे। एफपीओ के जरिये 4,300 करोड़ रुपये जुटाए गए, जिसका इस्तेमाल कंपनी ने कर्ज चुकाने में किया।

शेयर बिक्री से कंपनी को न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता का अनुपालन करने में मदद मिलेगी

उत्कर्ष एसएफबी के आईपीओ को मिले 4.2 गुना आवेदन

उत्कर्ष स्मॉल फाइनैंस बैंक के आईपीओ को बुधवार को पहले दिन 4 गुना से ज्यादा आवेदन मिले। आईपीओ की खुदरा श्रेणी को पहले ही 12 गुना से ज्यादा बोली मिल चुकी है, वहीं एचएनआई श्रेणी में 7 गुना से ज्यादा आवेदन मिले। एक दिन पहले लेनदार ने एंकर निवेशकों को 25 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 223 करोड़ रुपये के शेयर आवंटित किए। आईपीओ का कीमत दायरा 23 से 25 रुपये प्रति शेयर है।

कीमत दायरे के ऊपरी स्तर पर उत्कर्ष एसएफबी का बाजार पूंजीकरण 2,740 करोड़ रुपये बैठता है। कंपनी इस आईपीओ में 500 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी कर रही है, जिसका इस्तेमाल बैंक के टियर-1 पूंजी आधार को मजबूत बनाने में किया जाएगा। *बीएस*

अलविदा एचडीएफसी, स्वागत नए दिग्गज का

विलय के बाद बनने वाला एचडीएफसी बैंक गुरुवार से आकार ले लेगा, वहीं उसकी मूल कंपनी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनैंस कॉरपोरेशन (एचडीएफसी) का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। नई इकाई का बाजार पूंजीकरण 12.5 लाख करोड़ रुपये होगा, जो उसे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद दूसरी सबसे मूल्यवान फर्म बना देगा। आरआईएल का एमकैप अभी 18.5 लाख करोड़ रुपये है।

हालांकि ज्यादा फ्री-फ्लोट के कारण एचडीएफसी बैंक बेंचमार्क निफ्टी व सेंसेक्स में सबसे ज्यादा भारांक वाले आरआईएल को पीछे धकेल देगा। नुवामा के मुताबिक विलय के बाद बनने वाली इकाई का निफ्टी में 14.43 फीसदी भारांक होगा, जो आरआईएल के मुकाबले 363 आधार अंक ज्यादा होगा। बैंक निफ्टी इंडेक्स में एचडीएफसी बैंक का भारांक बढ़कर 29.1 फीसदी हो जाएगा।

एचडीएफसी के शेयरधारकों को विलय के बाद बनी इकाई के शेयर जारी होने में 10-12 दिन लग सकते हैं और तभी यह डीमैट में नजर आएगा। बाजार के प्रतिभागियों ने यह जानकारी दी। लेकिन इंडेक्स कंपोजिशन व ट्रेडिंग के लिहाज से एचडीएफसी बैंक को गुरुवार से विलय के बाद बनने वाली इकाई के तौर पर माना जाएगा। विलय के बाद बने एचडीएफसी बैंक के 7.53 अरब शेयर होंगे। विलय के कारण एचडीएफसी के 1.85 अरब शेयर एचडीएफसी बैंक के 3.1 अरब शेयरों के रूप में तब्दील किए जाएंगे। मूल कंपनी एचडीएफसी की एचडीएफसी बैंक में शेयरधारिता समाप्त हो जाएगी।

150 अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ एचडीएफसी बैंक वैश्विक स्तर पर चौथा और एशिया में दूसरा सबसे बड़ा मूल्यवान बैंक बन जाएगा। साथ ही लेनदार देश में सबसे लाभकारी कॉरपोरेशन में से एक बन जाएगा। प्रो-फोर्मा के आधार पर विलय के बाद बने एचडीएफसी बैंक का शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 23 में 60,348 करोड़ रुपये था। इस बीच, आरआईएल ने वित्त वर्ष 23 में 66,702 करोड़ रुपये का एकीकृत शुद्ध लाभ दर्ज किया जबकि आईसीआईसीआई बैंक ने 34,037 करोड़ रुपये।

समी मोडक

नया सवेरा

गुरुवार से एचडीएफसी बैंक का बेंचमार्क सूचकांकों में सबसे ज्यादा भारांक होगा और यह भारत की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी होगी

बैंक	एमकैप (लाख करोड़ रु.) फ्री फ्लोट	कुल	निफ्टी भारांक फीसदी
एचडीएफसी बैंक*	12.36	12.49	14.43
रिलायंस	9.25	18.50	10.80
आईसीआईसीआई बैंक	6.63	6.63	7.75
इन्फोसिस	4.74	5.52	5.54
आईटीसी	4.11	5.79	4.80
टीसीएस	3.35	11.97	3.91
एलऐंडटी	2.95	3.43	3.44
कोटक बैंक	2.74	3.71	3.20
ऐक्सिस बैंक	2.64	2.97	3.08
एचयूएल	2.37	6.24	2.77

स्रोत : नुवामा, ब्लूमबर्ग *विलय के बाद बनी इकाई
संकलन : बीएस रिसर्च ब्यूरो

जीएसटी की चोट से फिसले डेल्टा और नजारा के शेयर

दीपक कोरगांवकर और पुनीत वाधवा
मुंबई/नई दिल्ली, 12 जुलाई

डेल्टा कॉर्प और नजारा टेक्नोलॉजिज के शेयर बीएसई पर बुधवार के कारोबारी सत्र में 14 फीसदी तक टूट गए क्योंकि जीएसटी परिषद ने मंगलवार को ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और हॉर्स रेसिंग पर एक समान 28 फीसदी कराधान की मंजूरी दे दी।

जीएसटी संभवतः पूरी कारोबार वैल्यू पर लगाया जाएगा, जो प्लेटफॉर्म पर दांव की पूरी वैल्यू है।

वैयक्तिक शेयरों की बात करें तो डेल्टा पर कारोबारी सत्र के शुरुआती दौर में 10 फीसदी का लोअर सर्किट लगा और यह 222.15 रुपये का रह गया और इसमें सिर्फ विक्रेता ही नजर आए। कुल मिलाकर 6.80 लाख शेयरों का कारोबार हुआ। एनएसई व बीएसई पर कुल 2.32 करोड़ शेयरों के पेंडिंग सेल ऑर्डर थे।

भारी वॉल्यूम के कारण नजारा टेक का शेयर कारोबारी सत्र में 14 फीसदी टूटकर 605 रुपये पर आ गया। अभी यह शेयर बीएसई पर 6 फीसदी नीचे है। इसमें औसत ट्रेडिंग वॉल्यूम पांच गुना उछल गया। कुल मिलाकर एनएसई व बीएसई पर 25 लाख शेयरों का कारोबार हुआ। केपीएमजी इंडिया के पार्टनर व उप-प्रमुख (अप्रत्यक्ष कर) संतोष दलवी ने कहा, इस फैसले से गेमिंग इंडस्ट्री पर असर पड़ सकता है, जिसमें विदेशी एंटरप्राइजेज शामिल हैं। जीएसटी के चलते ऐसी कंपनियों को पिछली अवधि समेत अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है क्योंकि यह संशोधन आसानी से समझने योग्य है। स्टॉक एक्सचेंज को भेजी सूचना में नजारा ने स्पष्ट किया कि जब यह कर लागू होगा तब सिर्फ उसके कारोबार के स्किल आधारित रियल मनी गेमिंग पर ही लागू होगा। 2022-23 में कंपनी के कुल एकीकृत राजस्व में इस सेगमेंट का योगदान 5.2 फीसदी था। नजारा ने कहा, कारोबार के इस सेगमेंट पर संभावित असर को कम करने के लिए हम कदम उठाएंगे और हमारा अनुमान है कि कुल राजस्व पर इसका न्यूनतम असर होगा।

आईडीबीआई कैपिटल के शोध प्रमुख ए के प्रभाकर ने कहा, निवेशक के नजरिये से देखें तो यह कदम शेयरधारकों व कंपनियों को झटका दे सकता है। उन्होंने कहा, कराधान की ऐसी ऊंची दर बाजारों को पसंद नहीं आया और संबंधित शेयरों में तेज गिरावट आई। निवेशकों व कंपनियों को 28 फीसदी कराधान से नुकसान होगा। मोटे तौर पर बाजार वैसी कंपनियों व शेयरों को पसंद नहीं करता, जहां बहुत ज्यादा विनियमन व उच्च कराधान हो। निवेशकों को कम से कम अभी इन शेयरों को लेकर स्पष्ट रुख रखना चाहिए। इस बीच, भारत का ऑनलाइन गेमिंग बाजार रियल मनी गेम व नॉन रियल मनी गेम में बंटा हुआ है। रियल मनी वाला गेम स्किल आधारित होता है, जिसे रियल मनी के लिए खेला जा सकता है। नॉन रियल मनी वाले गेम वे होते हैं जहां वास्तविक रकम शामिल नहीं होती। अभी रमी, पोकर और फैंटेसी आदि रियल मनी गेम की श्रेणी में अग्रणी गेम हैं। नॉन-रियल मनी वाले गेम हाइपर कैजुअल व कैजुअल और मिडकोर व हार्डकोर गेम में बंटे हुए हैं, जो लर्निंग कर्व व मुश्किलों के विभिन्न स्तरों पर आधारित है।

ट्रेजरी बिल की नीलामी में उम्मीद से कम मांग

अंजलि कुमारी
मुंबई, 12 जुलाई

बुधवार को हुई ट्रेजरी बिल की नीलामी में उम्मीद से कम मांग रही, जिसका कारण व्यवस्था में नकदी के सख्त हालात हैं। डीलरों ने यह जानकारी दी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन के ट्रेजरी बिल का कटऑफ प्रतिफल क्रमशः 6.74 फीसदी, 6.87 फीसदी और 6.88 फीसदी तय किया है। 91 दिन वाले ट्रेजरी बिल का कटऑफ प्रतिफल 2 आधार अंक ज्यादा, वहीं 182 दिन के ट्रेजरी बिल का कटऑफ प्रतिफल पिछले हफ्ते के मुकाबले 4 आधार अंक ज्यादा था। हालांकि 364 दिन के ट्रेजरी बिल का कटऑफ प्रतिफल पिछले हफ्ते के मुकाबले 3 आधार अंक कम था।

प्राइमरी डीलरशिप के एक डीलर ने कहा, पिछले हफ्ते सरकारी खर्च व अन्य वजहों से नकदी की स्थिति बेहतर थी। अब हम देख सकते हैं कि नकदी के चलते ओवरनाइट दरें भी चढ़ गई हैं। ताजा आंकड़े बताते हैं कि बैंकों ने आरबीआई के पास मंगलवार को करीब 1.3 लाख करोड़ रुपये जमा कराए। यह 4 जुलाई को 2.3 लाख करोड़ रुपये था। ओवरनाइट वेटेड एवरेज कॉल रेट बुधवार को 6.46 फीसदी था, जो 5 जुलाई को 6.41 फीसदी रहा था। सरकारी बैंक के एक डीलर ने कहा, मांग-आपूर्ति के मसले के अलावा नकदी की ट्रेजरी बिल के कटऑफ में अहम भूमिका होती है। बाजार 91 दिन वाले बिल के लिए करीब 70-71 फीसदी, 182 दिन के लिए करीब 82 फीसदी और एक साल वाले बिल के लिए 85-86 फीसदी की उम्मीद कर रहा था।

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

INITIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES ON THE MAIN BOARD OF THE STOCK EXCHANGES IN COMPLIANCE WITH CHAPTER II OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BAORD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL DISCLOSURES REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("SEBI ICDR REGULATIONS")

PUBLIC ANNOUNCEMENT

PLATINUM.

(Please scan this QR Code to view the DRHP)

PLATINUM INDUSTRIES LIMITED

Our Company was incorporated under the provisions of the Limited Liability Partnership Act, 2008 in the name and style of "Platinum Industries LLP" on August 19, 2016. Platinum Industries LLP was thereafter converted into a private limited company "Platinum Industries Private Limited" pursuant to the provisions of Chapter XXI of the Companies Act, 2013 vide Certificate of Incorporation dated July 09, 2020 issued by the Central Registration Centre, Registrar of Companies. Subsequently, our Company has been converted into a public limited company and the name of our Company changed to "Platinum Industries Limited" pursuant to a special resolution passed at the Extra-Ordinary General Meeting of our Company held on March 31, 2023 and a fresh Certificate of Incorporation dated June 02, 2023 has been issued by the RoC, please refer to the section titled "History and Certain Corporate Matters" beginning on page 205 of the Draft Red Herring Prospectus dated July 11, 2023 **("DRHP").**

Registered Office: Unit No. 841, 4th Floor, Solitaire Corporate Park-8 Andheri Kurla Road, Andheri(E), Mumbai - 400093, Maharashtra, India.
Telephone: +917304538055; **Website:** www.platinumindustriesltd.com
Contact Person: Bhagyashree Amit Mallawat, Company Secretary and Compliance Officer; **E-mail:** cs@platinumindustriesltd.com
Corporate Identity Number: U24299MH2020PLC341637

PROMOTERS OF OUR COMPANY : KRISHNA DUSHYANT RANA AND PARUL KRISHNA RANA

INITIAL PUBLIC OFFER OF UP TO 15,903,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH ("EQUITY SHARES") OF PLATINUM INDUSTRIES LIMITED ("COMPANY" OR "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING UP TO ₹ [●] MILLION ("ISSUE"). THE ISSUE SHALL CONSTITUTES ₹ [●] % OF THE FULLY-DILUTED POST- ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BRLM, MAY CONSIDER A PRE-IPO PLACEMENT OF SPECIFIED SECURITIES, AS MAY BE PERMITTED UNDER THE APPLICABLE LAW, AGGREGATING UP TO ₹ 150.00 MILLION, PRIOR TO FILING OF THE RED HERRING PROSPECTUS WITH THE ROC. THE PRE-IPO PLACEMENT, IF UNDERTAKEN, WILL BE AT A PRICE TO BE DECIDED BY OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BRLM. IF THE PRE-IPO PLACEMENT IS COMPLETED, THE AMOUNT RAISED PURSUANT TO THE PRE-IPO PLACEMENT WILL BE REDUCED FROM THE ISSUE, SUBJECT TO COMPLIANCE WITH RULE 19(2)(B) OF THE SCRR, AS AMENDED.

THE FACE VALUE OF EQUITY SHARES IS ₹ 10 EACH. THE ISSUE PRICE IS ₹ [●] TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGER AND WILL BE ADVERTISED IN ALL EDITIONS OF ₹ [●] AND ALL EDITIONS OF ₹ [●] (WHICH ARE WIDELY CIRCULATED ENGLISH DAILY NEWSPAPER AND HINDI DAILY NEWSPAPER, AND ₹ [●] EDITIONS OF THE MARATHI REGIONAL NEWSPAPER (MARATHI BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF MAHARASHTRA, WHERE OUR REGISTERED OFFICE IS LOCATED), AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/ ISSUE OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO BSE LIMITED ("BSE") AND NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE", AND TOGETHER WITH BSE, THE "STOCK EXCHANGES") FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES IN ACCORDANCE WITH THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED (THE "SEBI ICDR REGULATIONS").

In case of any revision to the Price Band, the Bid/ Issue Period will be extended by at least three additional Working Days following such revision of the Price Band, subject to the Bid/ Issue Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company, in consultation with the Book Running Lead Manager, may for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/Issue Period for a minimum of three Working Days, subject to the Bid / Issue Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/ Issue Period, if applicable, will be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a public notice, and also by indicating the change on the respective websites of the Book Running Lead Manager and at the terminals of the Syndicate Members and by intimation to Self-Certified Syndicate Banks ("**SCSBs**"), other Designated Intermediaries and the Sponsor Banks, as applicable.

The Issue is being made in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("**SCRR**") read with Regulation 31 of the SEBI ICDR Regulations. The Issue is being made through the Book Building Process in accordance with Regulation 6(1) of the SEBI ICDR Regulations, wherein not more than 50% of the Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIB Portion"), provided that our Company, in consultation with the Book Running Lead Manager, may allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors and the basis of such allocation will be on a discretionary basis by our Company, in consultation with the BRLM, in accordance with the SEBI ICDR Regulations (the "**Anchor Investor Portion**"), of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from the domestic Mutual Funds at or above the price at which allocation is made to Anchor Investors ("**Anchor Investor Allocation Price**"). In the event of under-subscription or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the QIB Portion (other than the Anchor Investor Portion) (the "**Net QIB Portion**"). Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. Further, not less than 15% of the Issue shall be available for allocation to NIIs ("Non-Institutional Category") of which one-third of the Non-Institutional Category shall be available for allocation to Bidders with an application size of more than ₹0.20 million and up to ₹1.00 million and two-thirds of the Non-Institutional Category shall be available for allocation to Bidders with an application size of more than ₹1.00 million and under-subscription in either of these two sub-categories of Non-Institutional Category may be allocated to Bidders in the other sub-category of Non-Institutional Category in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. Further, not less than 35% of the Issue shall be available for allocation to RIIs ("**Retail Category**"), in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Issue Price. All Bidders (except Anchor Investors) shall mandatorily participate in this Issue only through the Application Supported by Blocked Amount ("**ASBA**") process and shall provide details of their respective bank account (including UPI ID (defined hereinafter) in case of UPI Bidders (defined hereinafter) in which the Bid Amount will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("**SCSBs**") or the Sponsor Bank(s), as the case may be. Anchor Investors are not permitted to participate in the Anchor Investor Portion through the ASBA process. For details, see "*Issue Procedure*" on page 358 of the DRHP.

This public announcement is being made in compliance with the provisions of regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that our Company is proposing, subject to applicable statutory and regulatory and requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offering of its Equity Shares and has filed the DRHP dated July 11, 2023 with the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**") on July 12, 2023.

Pursuant to Regulation 26(1) of SEBI ICDR Regulations, the DRHP filed with SEBI shall be made public for comments, if any, for a period of at least 21 (twenty one) days from the date of such filing, by hosting it on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, the BRLM at www.unistonecapital.com, our Company at www.platinumindustriesltd.com, and the Stock Exchanges where the Equity Shares are proposed to be listed, i.e. BSE at www.bseindia.com and NSE at www.nseindia.com. Our Company hereby invites the public to give their comments on the DRHP filed with SEBI in respect of disclosures made in the DRHP. The public is requested to send a copy of the comments sent to SEBI, to the Company Secretary and Compliance Officer of our Company and the BRLM at their respective addresses mentioned herein. All comments must be received by our Company or the BRLM in relation to the Issue on or before 5 p.m. on the 21st day from the aforementioned date of filing of the DRHP with SEBI.

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and Bidders should not invest any funds in the Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Bidders are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Issue. For taking an investment decision, Bidders must rely on their own examination of our Company and the Issue, including the risks involved. The Equity Shares in the Issue have neither been recommended, nor approved by the SEBI, nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the DRHP. Specific attention of the Bidders is invited to "Risk Factors" beginning on page 36 of the DRHP.

Any decision to invest in the equity shares described in the DRHP may be made after a Red Herring Prospectus ("RHP") has been registered with the RoC and must be made solely on the basis of such RHP as there may be material changes in the RHP from the DRHP.

The Equity shares, when offered through the RHP, are proposed to be listed on Stock Exchanges.

For details of the main objects of our Company as contained in the Memorandum of Association, please see "History and Certain Corporate Matters" beginning on page 205 of the DRHP.

The liability of the members of our Company is limited by shares.

For details of the share capital and capital structure of our Company and the names of the signatories of the Memorandum of Association and the number of shares of our Company subscribed by them, please see "*Capital Structure*" beginning on page 90 of the DRHP.

BOOK RUNNING LEAD MANAGER	REGISTRAR TO THE OFFER
UNISTONE **UNISTONE CAPITAL PRIVATE LIMITED** A/ 305, Dynasty Business Park, Andheri-Kurla Road, Andheri East, Mumbai - 400 059, India. **Telephone:** +91 9820057533 **Email:** mb@unistonecapital.com **Investor grievance email:** compliance@unistonecapital.com **Contact Person:** Mr. Brijesh Parekh **Website:** www.unistonecapital.com **SEBI registration number:** INM000012449 **CIN:** U65999MH2019PTC330850	**BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED** S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400 093, Maharashtra, India. **Telephone:** 022 - 62638200 **Facsimile:** 022 - 63638280 **Email:** ipo@bigshareonline.com **Investor grievance email:** investor@bigshareonline.com **Contact Person:** Mr. Babu Rapheal C. **Website:** www.bigshareonline.com **SEBI Registration Number:** INR000001385 **CIN:** U99999MH1994PTC076534U

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed in the DRHP.

For Platinum Industries Limited
On behalf of Board of Directors
Sd/-
Bhagyashree Amit Mallawat
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Mumbai, Maharashtra
Date: : July 12, 2023

PLATINUM INDUSTRIES LIMITED *is proposing, subject to applicable statutory and regulatory and requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offering of its Equity Shares and has filed the DRHP dated July 11, 2023, with SEBI on July 12, 2023. The DRHP shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, NSE at www.nseindia.com, BSE at www.bseindia.com and the website of the BRLM at www.unistonecapital.com and our Company at www.platinumindustriesltd.com. Any potential investor should note that the investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to risk, please see to the section titled "Risk Factors" of the RHP, when filed. Potential investors should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decisions. Specific attention of the Investors is invited to "Risk Factors" beginning on page 36 of the DRHP.*

*The Equity Shares offered have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act, 1933, as amended ("**U.S. Securities Act**") or any other applicable laws in the United States and, unless so registered, may not be offered or sold within the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Equity shares are being offered and sold outside the United States in offshore transactions as defined in and in reliance on regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdictions where those offers and sales are made. The Equity Shares have not been and will not be registered, listed or otherwise qualified in any other jurisdiction outside India and may not be issued or sold, and Bids may not be made by persons in any such jurisdiction, except in compliance with the applicable laws of such jurisdiction.*